

भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 3
उत्तर देने की तारीख: 18.07.2022

मध्याह्न भोजन लंबित बिल

+3. श्री राम मोहन नायडू किंजरापु:

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) मध्याह्न भोजन योजना (जिसका हाल ही में नाम बदलकर प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना किया गया है) से संबंधित आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के भुगतान किए जाने वाले अब तक लंबित बिलों का जिले-वार ब्यौरा क्या है; और
(ख) इन लंबित बिलों के भुगतान में देरी, यदि कोई है, के क्या कारण हैं?

उत्तर
शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अन्नपूर्णा देवी)

(क) और (ख): आंध्र प्रदेश राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, रसोइया-सह-सहायकों को मानदेय और खाना पकाने की लागत के लिए 1,83,70,785/- रुपये की राशि का भुगतान किया जाना बाकी है। जिलेवार विवरण अनुलग्नक में संलग्न है। सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के माध्यम से एकल नोडल एजेंसी के खाते में राज्य सरकार द्वारा पर्याप्त बजट जारी किया गया है। हालांकि, इन लंबित बिलों के भुगतान में देरी बैंकों में कुछ तकनीकी कारणों और खाना पकाने वाली एजेंसियों के बदलाव के कारण हुई है।

मध्याह्न भोजन के लंबित बिल के संबंध में माननीय सांसद श्री राम मोहन नायडू किंजरापु द्वारा उठाए गए दिनांक 18.07.2022 के लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत आंध्र प्रदेश में जिले-वार लंबित बिल

(रुपये में)

क्र.सं.	जिले का नाम	लंबित बिल		
		खाना पकाने की लागत	मानदेय	कुल
1.	विशाखापत्तनम	11,61,130	3,35,000	14,96,130
2.	पूर्वी गोदावरी	58,50,345	30,26,000	88,76,345
3.	पश्चिमी गोदावरी	7,68,866	4,57,000	12,25,866
4.	कृष्णा	63,973	27,000	90,973
5.	प्रकाशम	3,318	40,000	43,318
6.	चित्तूर	59,47,976	1,51,000	60,98,976
7.	कडपा	3,10,464	98,000	4,08,464
8.	अनंतपुर	1,13,713	17,000	1,30,713
	कुल	1,42,19,785	41,51,000	1,83,70,785